

मामलों का विवरण

आर. श्रीनिवास बनाम

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील सं. 859) सितंबर 06,2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय यदि निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने में न्यायसंगत साबित होता है तो अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उसे दोषमुक्त करने से यू/एस. एस. लागू होता है।³⁰² और भारतीय दण्ड संहिता सी. 201, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा था कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-कब लागू नहीं किया जा सकता है:

आयोजित किया गया: 'लास्ट सीन' सिद्धांत को तभी लागू किया जा सकता है जब वही स्टैंड उचित संदेह से परे साबित हों-वर्तमान मामले में, लास्ट सीन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है और वह सिद्धांत ही संदेह में है-साथ ही, कथित लास्ट सीन और शरीर की बरामदगी के बीच एक लंबा समय-अंतराल है-इसके अलावा, तैयार किए गए आरोप और गवाहों के बयान में बड़ी विसंगति है-विशिष्ट सी आरोप कि सह-आरोपी वह था जिसने मृतक को उसके घर से ले गया था, जबकि बयान के दौरान मृतक की पत्नी और उसके भाई ने कहा कि यह अपीलकर्ता था जिसने मृतक को ले गया था, इस तरह के बयानों की सत्यता और प्रामाणिकता के संबंध में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है-साथ ही, तथ्य यह है कि

55 56

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

साक्ष्य के मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह अपीलार्थी का अपराध है-ऐसे साक्ष्य पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित है, जहां श्रृंखला अधूरी है-निर्दोषता का अनुमान अभियुक्त के पक्ष में है और जब संदेह पैदा होता है, तो लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है, न कि अभियोजन पक्ष को-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।[पैरा 13,15,16 और 17]

अभ्यास और प्रक्रिया-दोषमुक्ति-अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप:

आयोजित किया गया: बरी किए जाने के मामले में एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है-जब दो विचार संभव होते हैं, तो अभियुक्त का पक्ष लेने वाले को अपराधिक कानून पर निर्भर होना चाहिए। [पैरा 18]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राजस्थान राज्य बनाम काशी राम, (2006) 12 एससीसी 254:[2006] 8 पूरका.एस. सी. आर. 501-लागू नहीं है।

कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 715:[2014] 3 एससीआर

744; निजाम बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 एस. सी. सी. 550:[2015] 10 एससीआर 786;

चोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 742; लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 399; चंद्रप्पा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 742; लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 399; चंद्रप्पा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 742; लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 399।

कर्नाटक, (2007) 4 एससीसी 415:[2007] 2 एस. सी. आर. 630; जाफरुद्दीन बनाम केरल राज्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 440-पर भरोसा किया।

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; शैलेंद्र राजदेव पासवन बनाम गुजरात राज्य,

(2020) 14 एससीसी 750:[2019] 14 एस. सी. आर. 270; सुरेश थिपमप्पा शेटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2023 आई. एन. एस. सी. 749-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील No.859।

सी. आर. एल. में बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.10.2010 के निर्णय और आदेश से। 2005 का ए. No.1952।

आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य 58

सुश्री किरण सूरी, सीनियर। अधिवक्ता, एस. जे. अमित, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, सुश्री विदुषी गर्ग, कृष्ण कुमार, बी. पुरुषोत्तमा रेड्डी, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमन पंवार, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, शिवम सिंह बाघल, वरुण वर्मा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे.

पक्षकारों की विद्वान विद्वान अधिवक्ता सुनी।

2. सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के तहत वर्तमान आपराधिक अपील, सीआरएल में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.10.2010 के खिलाफ निर्देशित है। ए. बेंगलुरु में कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा पारित (जिसे इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया है) (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसके तहत उच्च न्यायालय ने राज्य के नेतृत्व में अपील को अनुमति देने के लिए प्रसन्न था।

वास्तविक प्रिज्म:

3. अपीलार्थी एक अन्य के साथ सह-अभियुक्त था। सुनवाई के बाद दोनों को बरी कर दिया गया। हालाँकि, कर्नाटक राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष की गई अपील में, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी." के रूप में संदर्भित) की धारा 302 1 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 03.01.2002 पर लगभग 4 बजे:30 पी. एम., एक पुरुष का अज्ञात मृत शरीर वादी (पी. डब्ल्यू. 1) को अपने अंतिम संस्कार में मिला, जिससे पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। बाद में, शव की पहचान एक कृष्णप्पा के रूप में की गई। आरोप यह है कि अभियुक्त सं. 1 (यहाँ अपीलार्थी) के साथ अभियुक्त सं. 2 के साथ

1 302. हत्या के लिए सजा।— जो कोई भी हत्या करता है उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और वह दंडनीय भी होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

इरादे ने मृतक को मार डाला। उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह था कि मृतक ने अपीलार्थी की बहन के साथ अवैध अंतरंगता विकसित की थी। यह आरोप लगाया जाता है कि दोनों अभियुक्तों ने शव पर पेट्रोल छिड़ककर सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता/पीडब्लू1 और जाँच के प्रमाणकों में से एक सहित 12 गवाहों से शव का पंचनामा की।

5. मुकदमे पर, प्रधान सत्र न्यायाधीश, बेंगलूर ग्रामीण जिला, बेंगलूर ने निर्णय और आदेश दिनांक 09.06.2005 द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 और 201 के तहत बरी कर दिया, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और वह अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को साबित करने में भी विफल रहा था।

6. दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से व्यथित कर्नाटक राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की अपराधिक अपील 2 का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को बरी करने के आदेश को उलट दिया, जबकि सह-अभियुक्त-अभियुक्त संख्या 2 (जिसे इसके बाद "ए 2" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील में इसे चुनौती दी गई है।

आवेदन की प्रस्तुतियाँ:

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का आधार साक्ष्य पर आधारित है और दिए गए कारण यह अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस हैं कि अभियोजन पक्ष भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 और 201 2 के तहत अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा था। यह आगे प्रस्तुत किया गया था

2 201. सबूत के गायब होने का कारण बनना, या गलत जानकारी देना

एंडर को बंद करें।— जो कोई भी, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने का कोई भी सबूत गायब कर देता है, कानूनी सजा से बचाव करने वाले की जांच करने के इरादे से, या उस इरादे से अपराध के संबंध में कोई जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है,

अगर एक कैपिटल ऑफ एनस।— यदि वह अपराध जिसे वह जानता है या मानता है कि किया गया है, मृत्यु से दंडनीय है, तो उसे सात वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह दंडनीय भी होगा।

यदि आजीवन कारावास से दंडनीय है।— और यदि दंडनीय है

आजीवन कारावास, या कारावास जो दस वर्ष तक बढ़ सकता है, किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, और दंडनीय भी होगा।

यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है।— और अगर ऑफ एनस है

दस वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय, अपराध के लिए दिए गए विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, एक अवधि के लिए जो 59 वर्ष तक बढ़ सकती है।

आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 60

कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ दोषमुक्ति के आदेश को उलटने में गलती की, जबकि ए 2 के दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मूल रूप से, दोनों को सौंपी गई भूमिका समान है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोप में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विशिष्ट आरोप यह था कि ए 2 वह व्यक्ति था जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दो दिन पहले मृतक के घर आया था और उसे इस बहाने से ले गया था कि अपीलार्थी के पिता उससे मिलना चाहते थे, जबकि बयान के दौरान, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 8 ने कहा है कि यह अपीलार्थी ही था जो आया था और मृतक को अपने साथ ले गया था।

9. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह बहुत ही बुनियादी पहलू जो अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल देता है, उसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषसिद्धि नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटने का एकमात्र आधार है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह मानने के लिए एकमात्र सामग्री कि मृतक को आखिरी बार उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के साथ देखा गया था, पीडब्लू 10 की गवाही थी, वह भी पुलिस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित थी, जब मुकदमे के दौरान पीडब्लू 10 मुकर गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि पी. डब्ल्यू. 10 की गवाही पर इस तरह की निर्भरता गलत है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित बरामदगी भी साबित नहीं हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह साबित करने के लिए कोई फोरेंसिक जांच नहीं की गई थी कि खून मृतक का था। अपीलार्थी द्वारा पी. डब्ल्यू. 10 से पेट्रोल खरीदने का सिद्धांत, जो शत्रुतापूर्ण हो गया है, भी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थी को संदेह का लाभ उठाने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त है।

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मृतक की पत्नी ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि अपीलार्थी और मृतक के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और इस प्रकार, प्रबल शत्रुता के सिद्धांत को भी नकार दिया गया है।

कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग के लिए, या दंड के साथ, या दोनों के साथ।

चित्रण

ए, यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या कर दी है, बी को सजा से बचाने के इरादे से शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए सात साल के लिए किसी भी विवरण के कारावास के लिए उत्तरदायी है, और इसके लिए भी दंडनीय है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि दोनों पक्षों के बीच इतनी प्रबल शत्रुता होती, तो मृतक के लिए अपीलार्थी के साथ उसके घर जाने का कोई अवसर नहीं था और वह भी रात में देर से। यह आग्रह किया गया कि आरोपों (ओं) के झूठ का एक मजबूत संकेत यह तथ्य है कि मृतक की पत्नी ने बयान के दौरान स्वीकार किया कि जब मृतक दो-तीन दिनों तक नहीं लौटा तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की थी और इस तरह के आचरण का एक बहुत ही अस्पष्ट कारण यह कहते हुए दिया गया है कि पहले भी वह (मृतक) दो-तीन दिनों के लिए चला जाता था।

उत्तरदायी-राज्य की प्रस्तुतियाँ:

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय के समर्थन में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का एक मजबूत उद्देश्य था। राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया

राजस्थान राज्य बनाम काशी राम में इस न्यायालय का निर्णय, **(2006) 12**

एस. सी. सी. 254, पैराग्राफ 19-23 में प्रासंगिक है, इस प्रस्ताव के लिए कि एक बार जब आरोपी वह व्यक्ति पाया जाता है जिसके साथ मृतक को आखिरी बार देखा गया था, तो आरोपी पर यह समझाने की जिम्मेदारी होती है कि पीड़ित कहाँ गया था या घटना कैसे हुई थी:

‘19. राज्य के अधिवक्ता द्वारा किए गए निर्णयों पर भरोसा करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे साबित करने के लिए संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यह अंततः साक्ष्य की सराहना का विषय है और इसलिए, प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

20. जोसेफ बनाम केरल राज्य [(2000) 5 एस. सी. सी. 197:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 926] तथ्य यह थे कि मृतक एक स्कूल का कर्मचारी था। ग्रेसी की बहनों में से एक, मृतक का पति होने का प्रतिनिधित्व करने वाला अपीलार्थी सेंट मैरी कॉन्वेंट गया, जहाँ वह कार्यरत थी और एक झूठे बहाने पर कि उसकी माँ बीमार थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे कॉन्वेंट की प्रभारी बहन, अभि.सा. 5 की अनुमति से ले गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि बाद में अपीलार्थी ने न केवल उसके साथ बलात्कार किया और उसके गहने लूट लिए, बल्कि उसे गुजरने वाली ट्रेन से कुचलने के लिए रेल पटरी पर डाल दिया। यह भी एक तथ्य के रूप में पाया गया कि मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था

61

उसकी कंपनी, और अनुसंधान के दौरान अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी पर, मृतक के गहने, जो अपीलार्थी द्वारा अभि.सा. 11 को बेचे गए थे, जब्त कर लिए गए। यह साबित करने के लिए स्पष्ट सबूत थे कि उन गहनों को मृतक ने उस समय पहना था जब वह अपीलार्थी के साथ कॉन्वेंट से निकली थी। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, तो अपीलार्थी ने हर चीज से पूरी तरह से इनकार करने के अपने दृढ़ रवैये से उसे अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों को समझाने या स्पष्ट करने का भी प्रयास नहीं किया। ऐसे तथ्यों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पी. 205, पैरा 14) "तथ्यों के इस तरह के दोषपूर्ण लिंक, यदि बिल्कुल भी हों, तो केवल अपीलार्थी द्वारा ही स्पष्ट किए जा सकते थे, और किसी और द्वारा नहीं, वे व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से उसकी जानकारी में थे। हालांकि ही में, अदालतों ने बचाव याचिका के झूठ और अदालत को दिए गए झूठे जवाबों से, जब पूछताछ की गई, तो पाया कि अपराध से संबंधित व्यक्ति को जोड़ने के लिए आवश्यक आपराधिक परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस तरह के जवाबों द्वारा लापता लिंक प्रदान किए गए हैं (देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश [(2000) 1 एससीसी 471:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 263])। अभियुक्त-अपीलार्थी को जोड़ने के लिए वह लापता कड़ी, हम इस मामले में हर एक और सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों के स्पष्ट और स्पष्ट इनकार द्वारा प्रदान की गई है, जो हमारे विचार में, साबित तथ्यों पर पर्याप्त और उचित निश्चितता के साथ, अभियुक्त को मृत्यु और ग्रेसी की मृत्यु के कारण से जोड़ती है।"

21. राम गुलाम चौधरी बनाम बिहार राज्य [(2001) 8 एस. सी. सी. 311:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1546] मुकदमे में साबित हुए तथ्य यह थे कि मृतक लड़के पर अपीलार्थीगण द्वारा बेरहमी से हमला किया गया था। जब उनमें से एक ने घोषणा की कि लड़का अभी भी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए, तो उसकी छाती पर एक छुरा लगा हुआ था। इसके बाद, अपीलार्थीगण उस लड़के को ले गए जो उसके बाद जीवित नहीं देखा गया था। अपीलार्थीगण ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि लड़के को ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया। सवाल यह उठा कि क्या ऐसे तथ्यों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होती है। इस न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 320, पैरा 24)

"स्पष्टीकरण के अभाव में, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थीगण लड़के पर अपीलार्थीगण के परिवार के बच्चे का अपहरण और हत्या करने का संदेह कर रहे थे, यह अपीलार्थीगण को समझाना था कि उन्होंने उसे ले जाने के बाद उसके साथ क्या किया था। जब

अपहरणकर्ताओं ने अदालत से उस जानकारी को रोक दिया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए हर औचित्य है कि उन्होंने लड़के की हत्या की थी। भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन के बोझ को कम करना न हो, लेकिन यह धारा वर्तमान जैसे मामलों में लागू होगी, जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे मृत्यु के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपीलार्थीगण को अपने विशेष ज्ञान के आधार पर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है।” 22. सहदेवन बनाम राज्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 534:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 382] अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को साबित किया कि मृतक को 5-3-1985 की सुबह से उस दिन कम से कम शाम 5 बजे तक अपीलार्थीगण के साथ देखा गया था जब उसे उसके घर लाया गया था, और उसके बाद उसका शव 6-3-1985 की सुबह मिला था। ऐसे तथ्यों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 543, पैरा 19)

“इसलिए, अपीलार्थीगण के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अदालत को संतुष्ट करें कि वादिवेलु ने उनके साथ कैसे, कहाँ और किस तरह से संबंध तोड़ लिए। यह इस सिद्धांत पर है कि एक व्यक्ति जो आखिरी बार दूसरे की संगति में पाया जाता है, अगर बाद में लापता पाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ वह आखिरी बार पाया गया था, उसे उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी जिनमें वे अलग हुए थे। तत्काल मामले में अपीलार्थीगण इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में उन्होंने कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया है।”

23. अधिकारियों के साथ गुणा करना आवश्यक नहीं है। सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान अपने आप में स्पष्ट और स्पष्ट हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने कंपनी कैसे और कब अलग की। उसे एक ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो अदालत को संभावित और संतोषजनक लगे। यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए माना जाना चाहिए। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित मामले में यदि अभियुक्त 63 में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है।

आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 64

उस पर रखे गए बोझ का निर्वहन, जो उसके खिलाफ साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत के बोझ को स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह नियम निर्धारित करता है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुरूप किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो अदालत किसी भी स्पष्टीकरण को जोड़ने में उसकी विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकती है जो श्रृंखला को पूरा करती है। नैना मोहम्मद में इस सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया है, री. [ए. आई. आर. 1960 मैड 218:1960 क्रि एल. जे. 620] '।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। तथ्य यह है कि न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोप और गवाहों के बयान में बड़ी विसंगति है- विशिष्ट आरोप कि ए 2 वही था जो मृतक को उसके घर से ले गया था, जबकि बयान के दौरान मृतक की पत्नी और उसके भाई ने कहा है कि यह अपीलकर्ता था जिसने मृतक को ले गया था, इस तरह के बयानों की सत्यता और प्रामाणिकता के संबंध में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मृतक देर रात अपीलार्थी के घर जाने के लिए सहमत हो गया था, जब इस आरोप की पृष्ठभूमि में देखा गया कि दोनों के बीच कड़ी दुश्मनी थी, तो यह अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है। अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में संदेह पैदा करने वाली ये परिस्थितियाँ अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करती हैं जब मृतक के दो दिनों से अधिक समय से लापता होने के तथ्य का अनुमान लगाया जाता है, फिर भी न तो उसकी पत्नी और न ही उसके भाई ने मृतक को लापता बताया। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मृतक के परिवार ने यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया कि मृतक कहाँ गया था। मृतक की पत्नी ने गवाही दी है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और उन्होंने दुश्मनी का संकेत नहीं दिया है। 14. राज्य के विद्वान अधिवक्ता [काशी राम (उपरोक्त)] द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह तत्काल तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उक्त मामले में, 'अंतिम बार देखा गया' का तथ्य साबित हो गया था और इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसमें आरोपी, जिसकी कंपनी में पीड़ित को आखिरी बार देखा गया था, उसे यह बताना था कि क्या हुआ था। जबकि वर्तमान मामले में, यह तथ्य कि क्या मृतक वास्तव में इसके साथ गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अपीलार्थी, जिसके बाद उसका शव मिला था, साबित नहीं हुआ था, जैसा कि कानून में आवश्यकता है। काशी राम (ऊपर) में ही, यह बाद के पैराग्राफ से स्पष्ट है:

‘24.राज्य के अधिवक्ता के तर्क में काफी बल है कि इस मामले के तथ्यों में भी यह माना जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी को मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के बाद, यह साबित करने का बोझ उस पर था कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वे तथ्य उसके विशेष ज्ञान में थे। चूँकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। इसलिए, यह परिस्थिति परिस्थितियों की श्रृंखला में एक लापता कड़ी प्रदान करती है जो उचित संदेह से परे उसके अपराध को साबित करती है।’

(जोर दिया गया) 15.इसलिए अभियुक्त पर बोझ तभी पड़ेगा जब अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को साबित किया जाएगा। तत्काल मामले में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह अपने आप में संदेह है। यह इस न्यायालय के बाद के फैसलों से पता चलता है, जिसका हम विज्ञापन करेंगे:

(क) कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 715, जहाँ यह था नोट किया:

‘12.आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था। अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, केवल अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण न देने से ही अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का प्रमाण नहीं मिल सकता है।’

(बल दिया गया)

(ख) निजाम बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 एस. सी. सी. 550, प्रासंगिक चर्चा

काशी राम (ऊपर) को देखने के बाद अनुच्छेद 16-18 में निहित है:

‘16.उपरोक्त के आलोक में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नीचे दी गई अदालतें "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" का आह्वान करने में सही थीं। ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से, मृतक मनोज कथित तौर पर 23-1-2001 पर ट्रक DL 1 GA 5943 में चला गया। मृतक मनोज का शव 26-1-2001 पर बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष के पास 65 हैं

आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 66

उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था, लेकिन मनोज के साथ क्या हुआ है, इसके बारे में अभियुक्तों ने कोई प्रशंसनीय, ठोस स्पष्टीकरण नहीं

दिया है। यह ध्यान दिया जाए कि केवल तभी जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य की अवहेलना करके तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ जीवित देखा गया था, तो आरोपी के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है और तभी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आरोपी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित की जा सकती है।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान, अपीलार्थी-अभियुक्त ने मनोज के ट्रक संख्या में यात्रा करने से इनकार किया। डीएल 1 जीए 5943। जैसा कि पहले देखा गया है, मनोज का शव तीन दिनों के बाद केवल 26-1-2001 पर बरामद किया गया था। उस समय के बीच का अंतराल जब मनोज कथित तौर पर ट्रक नं. डी. एल. 1 जी. ए. 5943 और शरीर की वसूली इतनी छोटी नहीं है कि अपीलार्थीगण के खिलाफ एक निष्कर्ष निकाला जा सके। इस मोड़ पर, साक्ष्य से उभरने वाले एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शहजाद खान (पीडब्लू 4) द्वारा दिए गए बयान से मृतक का आंतरिक अंग (लिंग) रस्सी से बंधा हुआ था और उसके नथुने से खून बह रहा था। मानिया गाँव, वह स्थान जहाँ मनोज का शव बरामद किया गया था, कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग आनंद लेने के लिए आते हैं। 18. मनोज के ट्रक में छोड़े जाने और शव की बरामदगी और जिस स्थान और परिस्थितियों में शव बरामद किया गया था, उसके बीच के समय के अंतराल को देखते हुए, अन्य लोगों के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात के सबूत न होने पर कि अपीलार्थीगण और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और जब समय का अंतराल लंबा होगा, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा कि अपीलार्थी मनोज की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और मनोज की हत्या करने के दोषी हैं। जहां समय का अंतराल लंबा है, "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा; अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्य से पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित है। तथ्यों और साक्ष्यों से, हमें अंतिम देखे गए सिद्धांत की पुष्टि करने वाला कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है।'

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

16. निजाम (ऊपर) में सुनाई देने वाला चेतावनी पत्र महत्वपूर्ण है। 'लास्ट सीन' सिद्धांत को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वही स्टैंड उचित संदेह से परे साबित हों। छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 3-न्यायाधीशों की पीठ,

(2023) 6 एस. सी. सी. 742 ने निम्नानुसार राय दी:

‘15.यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उन्हें पहले यह स्थापित करना होगा कि "कोई भी तथ्य विशेष रूप से अपीलार्थी की जानकारी में था"।...’

(जोर दिया गया) 17.वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि अंतिम बार देखे गए व्यक्ति का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है और यह भी तथ्य है कि कथित अंतिम बार देखे गए व्यक्ति और शरीर की बरामदगी के बीच एक लंबा समय-अंतराल है, और अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूरी है कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह अपीलार्थी का अपराध है।लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एस. सी. सी. 399 में हमने शरद पर विचार किया था।

बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 और शैलेंद्र राजदेव पासवन बनाम गुजरात राज्य, (2020) 14 एससीसी 750,

अभिनिर्धारित किया कि '। परिस्थितिजनक साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला को सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर किया जा सके।' इसे बनाए रखना असुरक्षित होगा

ऐसे साक्ष्य पर अपीलार्थी का दोषसिद्धि, जहां श्रृंखला स्पष्ट रूप से अधूरी है।इसके अलावा, निर्दोष होने का अनुमान अभियुक्त के पक्ष में होता है और जब संदेह पैदा होता है, तो लाभ अभियुक्त को मिलता है, न कि अभियोजन पक्ष को।सुरेश थिपम्पा का उल्लेख किया जा सकता है।

शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य, **2023** आईएनएससी **749**। **18.**इसके अलावा, चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, **(2007) 4 एस. सी. सी.**

415, यह निर्धारित किया गया था कि एक अपीलीय अदालत को बरी होने के मामले में यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।इस बात पर भी जोर दिया गया कि जब दो विचार संभव हों, तो अभियुक्त का पक्ष लेने वाले विचार पर भरोसा किया जाना चाहिए।अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ हैं -

हाल ही में संक्षेप में जाफरुद्दीन बनाम केरल राज्य, **(2022) 8 एस. सी. सी. 440**

पैराग्राफ 25-27 पर।इन कारकों पर भी, विवादित निर्णय असमर्थनीय है।

आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

19. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलार्थी को उसके जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे